

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2017—वैशाख 1, शक 1939

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2017

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-12/2016/29-1 दिनांक 07.04.2017 से मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 प्रारूप नियम मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 07 अप्रैल 2017 प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप नियम का हिंदी अनुवाद एतद् द्वारा निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है :-

#### अधिसूचना

भोपाल, दिनांक : 07 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ 7-12/2016/29-1 चूंकि, राज्य सरकार की यह राय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का 20 के अधीन हितग्राहियों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का 20 की धारा 40 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में जाने हुए, राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 बनाना प्रस्तावित करती है। नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) की अपेक्षा अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिवस का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

उक्त नियमों के प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व, आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल को प्राप्त आपत्ति अथवा सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:-

### नियमों का प्रारूप

#### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 है।
- (2) इनका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।
- (3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

#### 2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20)
- (ख) 'अपीलार्थी' से अभिप्रेत है वह पक्ष जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करता है;
- (ग) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 16 के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष;
- (घ) 'शिकायत' से अभिप्रेत है एवं इसमें सम्मिलित है लिखित में अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रस्तुत ऐसा अभ्यावेदन जिसमें अधिनियम के क्रियान्वयन में दोष/कमियों के आरोप से संबंधित शिकायत अंतर्विष्ट हो;
- (ङ) 'जिला शिकायत निवारण अधिकारी' से अभिप्रेत है जिले में शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत किया गया जिले का कलेक्टर है;
- (च) 'खाद्य आयोग से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश अधिनियम के क्रियान्वयन की मानीटरिंग तथा पुनर्विलोकन के प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा, 16 के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग;

(छ) 'सदस्य' से अभिप्रेत राज्य खाद्य आयोग का सदस्य;

(ज) 'सदस्य सचिव' से अभिप्रेत है राज्य खाद्य आयोग का सदस्य सचिव;

(2) उन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम अथवा अन्य सुसंगत अधिनियमों/नियमों में उनके लिए समनुदेशित किया गया है।

3. **महिला सशक्तीकरण:** राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप परिवार की वरिष्ठतम महिलाओं के नाम को परिवार के मुखिया के रूप में दर्ज करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगी।

4. **आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र:**

(1) अधिनियम की धारा 14 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के भाग के रूप में शिकायतों के निवारण के प्रयोजन लिए जिला स्तर पर निम्न अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे :-

1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2.	जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
3.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	महिला एवं बाल विकास विभाग

(2) कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था संबंधित नोडल अधिकारी के पास लिखित में अथवा ई-मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट शिकायत क्रमांक दिनांक सहित दिया जाएगा एवं शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा।

(3) नोडल अधिकारी शिकायत प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर शिकायत का निराकरण करेगा।

(4) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन हितग्राही सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

5. **जिला शिकायत निवारण अधिकारी:** राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगी।

6. **जिला शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:-**

- (1) कोई भी पीडित व्यक्ति लिखित में अथवा ई-मेल के माध्यम से अथवा जिला शिकायत निवारण अधिकारी के यहां स्थापित शिकायत पेटी में अपनी लिखित शिकायत डाल कर जिला शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत दर्ज करा सकेगा।
  - (2) शिकायतों को संकलित करने और पंजी में दर्ज करने के लिए प्रतिदिन 4 बजे शिकायत पेटी खोली जाएगी।
  - (3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराए जाने की स्थिति में शिकायत दर्ज करने के पश्चात् पीडित व्यक्ति को उक्त शिकायत की एक पावती दी जाएगी।
  - (4) शिकायतकर्ता के विशिष्ट विवरण तथा संपर्क जानकारी के साथ दर्ज की जाएगी। किसी भी गुमनाम शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जाएगी।
  - (5) प्रत्येक शिकायत को दिनांक सहित एक विशिष्ट शिकायत क्रमांक आवंटित किया जाएगा।
- 7. शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया-**
- (1) प्राप्त प्रत्येक शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी यह जांच करेगा कि क्या शिकायत में आगे कार्यवाही हेतु कोई प्रथम दृष्टया सार तत्व है अथवा नहीं।
  - (2) यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया शिकायत में सार तत्व विद्यमान है, तो वह संबंधित अधिकारी अथवा व्यक्ति अथवा अभिकरण से सुसंगत दस्तावेजों सहित स्पष्टीकरण मांगेगा। अपेक्षित स्पष्टीकरण एवं दस्तावेज संबंधित अधिकारी/व्यक्ति/अभिकरण द्वारा पंद्रह दिवस के भीतर जिला शिकायत निवारण अधिकारी को उपलब्ध कराए जाएंगे।
  - (3) संबंधित अधिकारी अथवा व्यक्ति अथवा अभिकरण के स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी का शिकायत की सच्चाई के बारे में यह समाधान हो जाता है तो वह शिकायत प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर शिकायत का निराकरण करेगा। यदि शिकायत का कोई आधार नहीं पाया जाता है तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत को निरस्त करेगा।
  - (4) यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी को प्रतीत होता है कि प्रकरण में आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है तो वह;
    - (एक) राज्य सरकार के जिला स्तर पर किसी उपयुक्त अधिकारी से प्रकरण की जांच करा सकेगा एवं इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर शिकायत की प्राप्ति से 45 दिवस के भीतर विनिश्चय कर सकेगा;
    - (दो) यदि आवश्यक समझे तो शिकायतकर्ता एवं शिकायत से संबंधित अधिकारी/व्यक्ति/अभिकरण को किसी नियत तिथि पर अपना पक्ष रखने के लिए अवसर प्रदान कर सकेगा तथा उनकी सुनवाई एवं प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों पर विचार करते हुए मामले का विनिश्चय शिकायत प्राप्ति की तारीख से 45 दिवस के भीतर कर सकेगा।
  - (5) यदि सुनवाई हेतु नियत तारीख पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहता है तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत को निरस्त कर सकेगा अथवा मामले में जांच के लिए एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए विनिश्चय कर सकेगा। लेकिन यदि शिकायत

से संबंधित अधिकारी/व्यक्ति/अभिकरण, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा बुलाए गए निर्धारित दिनांक को अनुपस्थित रहता है, तो वह मामले की जांच के लिए एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए मामले का विनिश्चय कर सकेगा।

- (6) शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर विनिश्चय के संबंध में लिखित में अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, शिकायतकर्ता से इसकी पावती की पुष्टि के लिए व्यवस्था के साथ सूचित किया जाएगा।
- (7) यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी की यह राय है कि शिकायत का निराकरण करने में ऊपर उपखण्ड 4 में विहित समय से अधिक समय की आवश्यकता है तो शिकायतकर्ता को एक अंतरिम उत्तर विलंब के कारणों को उल्लेखित करते हुए भेजा जाएगा।
8. **जिला शिकायत निवारण अधिकारी की शक्तियां:**  
शिकायतों की जांच करते समय जिला शिकायत निवारण अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह किसी जिला/मैदानी स्तर के किसी अधिकारी/व्यक्ति से -  
 (क) ऐसी पुस्तकें, लेखा एवं दस्तावेज अथवा इस प्रकार अपेक्षित व्यक्तियों के नियंत्रण अथवा अभिरक्षा में भी कोई अन्य वस्तु को समक्ष में प्रस्तुत करने एवं उनका परीक्षण करने के लिए अनुमत करने जैसी कि मांग पत्र में विनिर्दिष्ट की जाए;  
 (ख) ऐसी सूचनाएं देने, जैसी कि आवश्यक हो;  
 की अपेक्षा कर सकेगा।
9. **आवधिक प्रतिवेदन :** जिला शिकायत निवारण अधिकारी प्रत्येक माह उनको प्राप्त एवं निराकृत शिकायतों का एक मासिक प्रतिवेदन आगामी माह के 15 तारीख तक राज्य सरकार को आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से भेजेगा।
10. **अपील:** जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी शिकायतकर्ता अथवा अधिकारी/व्यक्ति/अभिकरण आदेश के जारी होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर खाद्य आयोग के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।
11. **खाद्य आयोग:**  
 (1) अधिनियम की धारा 16 की अपेक्षाओं के अनुसार खाद्य आयोग के गठन के लिए राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदनों की संवीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनी समिति द्वारा संपादित की जाएगी। उक्त समिति एक पैनल तैयार करेगी। राज्य सरकार उक्त पैनल में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में और 5 अन्य को सदस्य के रूप में चयनित करेगी।  
 (2) अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्ता एवं अन्य सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएंगी।

- (3) राज्य सरकार आयोग को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारीवृंद उपलब्ध कराएगी।
- (4) कोई भी सदस्य राज्यपाल को संबोधित लिखित सूचना पत्र के माध्यम से अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा एवं उसकी एक प्रति खाद्य आयोग के अध्यक्ष को दी जाएगी।
- (5) आयोग की बैठक के संबंध में सूचना अध्यक्ष के निर्देश पर आयोग के सदस्य सचिव द्वारा जारी की जाएगी। आयोग बैठकों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देशों का निर्धारण स्वयं करेगा।

#### 12. जांच, पुनर्विलोकन एवं मॉनिटरिंग:

- (1) खाद्य आयोग स्वप्रेरणा से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर अधिनियम के अध्याय दो के अंतर्गत प्रावधानित हकदारी के उल्लंघनों की जांच कर सकेगा।
- (2) अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के पुनर्विलोकन एवं मॉनिटरिंग के लिए, आयोग राज्य शासन के संबंधित विभागों के अधिकारियों, अन्य संबंधित अभिकरणों, प्रख्यात गैर सरकारी संगठनों के साथ नियमित बैठकें करेगा एवं अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन को अपना परामर्श देगा।

#### 13. शिकायत एवं अपील दर्ज करने की प्रक्रिया:-

- (1) अधिनियम के अंतर्गत हकदारी के उल्लंघन से संबंधित शिकायत अथवा जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील, शिकायतकर्ता अथवा अपीलार्थी द्वारा खाद्य आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयोग के सदस्य सचिव को संबोधित करते हुए की जाएगी।
- (2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील नियम 8 के अंतर्गत विहित समयावधि के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) प्रत्येक अपील के साथ जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य ऐसे दस्तावेज जो अपील के आधार को समर्थित करते हैं, प्रस्तुत किये जाएंगे।
- (4) शिकायत अथवा अपील, शिकायतकर्ता के विनिर्दिष्ट विवरण तथा संपर्क की सूचना सहित प्रस्तुत की जाएगी।
- (5) किसी भी गुमानाम शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जाएगी।

#### 14. आयोग द्वारा शिकायत एवं अपीलों का निराकरण:

- (1) कोई शिकायत प्राप्त होने पर, आयोग जिला शिकायत निवारण अधिकारी से सहायक दस्तावेजों सहित उस पर एक रिपोर्ट मंगायेगा, जिसे 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
- (2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी की रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेजों को विचारण में लेते हुए, आयोग जिला शिकायत निवारण अधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस के भीतर शिकायत के निवारण हेतु उचित आदेश पारित करेगा।
- (3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, आयोग अपीलार्थी एवं प्रति-अपीलार्थी को अपना प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि,

- समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिए अवसर देगा और उन्हें सुनने के उपरांत अपील प्राप्त होने की दिनांक से तीस दिवस के भीतर अपील पर विनिश्चय करेगा।
- (4) सुनवाई की नियत तिथि पर, अपीलार्थी एवं प्रति-अपीलार्थी को आयोग के समक्ष उपस्थित होना बाध्यकारी होगा एवं ऐसा करने में असफल रहने की दशा में, आयोग अपने विवेक के आधार पर, या तो प्रकरण को खारिज करेगा अथवा एक पक्षीय जांच करेगा तथा अपील प्राप्त होने की दिनांक से तीस दिवस की अवधि के भीतर अपील पर विनिश्चय करेगा।
- (5) आयोग का आदेश, सदस्य सचिव अथवा आयोग द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से अधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- (6) आयोग आदेश की प्रतियां संबंधित पक्षकारों को आदेश पारित होने के 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
- (7) यदि आयोग की यह राय है कि अपील का निराकरण करने में 30 दिवस से अधिक समय की आवश्यकता है, तो अपीलार्थी को विलंब के कारणों को इंगित करते हुए एक अंतरिम उत्तर भेजा जाएगा।
15. **अभिलेख का अनुरक्षण:** आयोग द्वारा अपील एवं उनके निराकरण से संबंधित अभिलेख सहित समस्त अभिलेख का अनुरक्षण करेगा।
16. **स्टाम्प एवं लोगो:** आयोग का स्टाम्प एवं लोगो राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
17. **पारदर्शिता एवं जवाबदेही,-**
- (1) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समस्त जानकारी यथा- उचित मूल्य दुकान, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन के प्रदाय केन्द्र के नाम एवं पते तथा खाद्यान्न के आवंटन, उठाव एवं वितरण राज्य स्तर पर विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (2) योजना के अन्तर्गत चयनित एवं पात्र परिवारों की सूची जनसामान्य के अवलोकन हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों, शासकीय उचित मूल्य दुकानों एवं विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- (3) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत एक वर्ष के भीतर आवंटित एवं वितरित खाद्यान्न से संबंधित समस्त अभिलेख जनसामान्य के अवलोकन हेतु शासकीय उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
18. **स्कीमों का सामाजिक अंकेक्षण,-**
- (1) राज्य सरकार, अधिनियम में उल्लिखित स्कीमों के सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद को प्राधिकृत कर सकेगी।
- (2) सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने के संबंध में राज्य सरकार दिशा-निर्देश जारी कर सकेगी।
19. **सतर्कता समितियों का गठन,-**
- (1) अधिनियम के प्रावधानों एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, निम्नानुसार राज्य, जिला, विकासखण्ड

एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति:-

अध्यक्ष	मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
सदस्य	1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग 3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग 5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 6. आयुक्त, पंजीयक एवं सहकारी संस्थाएँ 7. आयुक्त, महिला सशक्तीकरण 8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन 9. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित 10. संचालक, मध्याह्न भोजन योजना 11. सर्वोच्च न्यायालय में आयुक्तों के खाद्य सुरक्षा मामलों में राज्य सलाहकार
सदस्य सचिव	12. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश।

(ख) जिला स्तरीय सतर्कता समिति-

अध्यक्ष	प्रभारी मंत्री, द्वारा मनोनीत जिले का अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/महिला विधायक
सदस्य	1. आयुक्त, नगरपालिक निगम 2. जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी 3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास 4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 5. उपायुक्त/सहायक आयुक्त सह जिला पंजीयक सहकारी समितियां 6. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण
सदस्य सचिव	7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अपर कलेक्टर जिस पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी का दायित्व न हो।

(ग) विकासखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति-

अध्यक्ष	जनपद पंचायत अध्यक्ष
---------	---------------------



- सदस्य
1. विकास खण्ड मुख्यालय की मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी
  2. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास
  3. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
  4. विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी
  5. सहायक आपूर्ति अधिकारी/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी
  6. जनपद पंचायत की खाद्य समिति का अध्यक्ष
  7. विकासखण्ड मुख्यालय की खाद्य समिति का अध्यक्ष
  8. जनपद अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो महिला सरपंच
  9. विकासखण्ड मुख्यालय के पात्रता श्रेणी परिवार के चार राशनकार्डधारी जिनमें से दो परिवार अन्त्योदय श्रेणी के हों (जनपद अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
  10. विकास खण्ड स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण निगरानी समिति के दो सदस्य
  11. सक्रिय स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन का एक प्रतिनिधि
- सदस्य सचिव 12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत),

(घ) उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति -

(एक) नगरीय क्षेत्र में -

- अध्यक्ष उस वार्ड का पार्षद जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकान अवस्थित है। दुकान से एक से अधिक वार्ड संबद्ध होने की दशा में अन्य वार्ड के पार्षद सह-अध्यक्ष होंगे।
- सदस्य
1. अनुसूचित जाति का बीपीएल राशनकार्डधारी
  2. अनुसूचित जनजाति का बीपीएल राशनकार्डधारी
  3. निःशक्त श्रेणी का बीपीएल राशनकार्डधारी
  4. अंत्योदय श्रेणी का राशनकार्डधारी
  5. उपरोक्त के अतिरिक्त, प्राथमिकता श्रेणी के अन्य परिवारों में से 4 सदस्य, इस प्रकार कुल 8 सदस्य जिनमें 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी। एक से अधिक वार्ड होने पर, प्रत्येक वार्ड का समान प्रतिनिधित्व होगा।
- सदस्य सचिव 6. उस नगरीय वार्ड का प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकान अवस्थित है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र में-

- अध्यक्ष उस पंचायत का सरपंच जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकान अवस्थित है। दुकान से एक से अधिक ग्राम पंचायत संबद्ध होने की दशा में अन्य पंचायत का सरपंच सह-अध्यक्ष होंगे।

- सदस्य 1. अनुसूचित जाति का बीपीएल राशनकार्डधारी  
 2. अनुसूचित जनजाति का बीपीएल राशनकार्डधारी  
 3. निःशक्त श्रेणी का बीपीएल राशनकार्डधारी  
 4. अंत्योदय श्रेणी का राशनकार्डधारी  
 5. उपरोक्त के अतिरिक्त, प्राथमिकता श्रेणी के अन्य परिवारों में से 4 सदस्य, इस प्रकार कुल 8 सदस्य में से 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी। प्रत्येक ग्रामसभा का समान प्रतिनिधित्व होगा।
- सदस्य सचिव 6. उस ग्राम पंचायत से संबंधित पंचायत सचिव जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकान अवस्थित है।

(2) सतर्कता समिति की कालावधि एवं कार्य:-

(क) राज्य शासन द्वारा, अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सतर्कता समिति 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, किन्तु स्थानीय निकायों/पंचायतों के नामित अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल उनकी निर्वाचन अवधि तक ही होगा।

(ख) सतर्कता समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे:-

(एक) अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन को नियमित मॉनीटर करना।

(दो) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उल्लंघन होने की दशा में, उचित मूल्य दुकान/ ब्लाक स्तरीय सतर्कता समिति जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करेगी, जिस पर कार्यवाही कर समितियों को अवगत कराया जायेगा।

(तीन) राज्य स्तरीय समिति की बैठक 3 माह में, जिला स्तरीय समिति की बैठक 2 माह में तथा विकासखण्ड एवं उचित मूल्य दुकान स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक माह में आयोजित की जाएगी।

(चार) उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष के बैठक में उपस्थित नहीं होने की दशा में समिति द्वारा निर्धारित वरिष्ठ अशासकीय सदस्य की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी।

(पांच) सतर्कता समिति, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को अधिनियम के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में लिखित में सूचित करेगी।

(3) दिवालिया/सिद्धदोष/अक्षम होने पर अशासकीय सदस्यों के समिति से हटाने की प्रक्रिया: अशासकीय सदस्यों के दिवालिया, अपराध में दोषसिद्ध अथवा शारीरिक या मानसिक रूप से कर्तव्य निर्वहन करने में असमर्थ होने या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की दशा में समिति के नियुक्तकर्ता द्वारा उसे हटाया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.